117 महिला लीडर्स के पास करोड़ों की संपत्ति

हुरुन इंडिया वुमन लीडर्स 2026 रिपोर्ट में 84% महिलाएं सेल्फ-मेड, रोशनी नादर सबसे बड़ी वेल्थ मल्टीप्लायर

नई दिल्ली, 31 जुलाई भारत में महिलाओं का नेतृत्व अब सिर्फ कारोबार और समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे संपत्ति और सफलता के नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही हैं. कैंडेरे हुरुन इंडिया वुमन लीडर्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार, देश की 117 प्रभावशाली महिला लीडर्स के पास कुल 39 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है.

इनमें 84 प्रतिशत महिलाओं ने यह मुकाम अपनी मेहनत और उद्यमिता के दम पर हासिल किया है, जो भारत में महिला नेतृत्व और आर्थिक सशक्तिकरण की मजबूत तस्वीर पेश करता है. हुरुन इंडिया वुमन लीडर्स 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष प्रभावशाली महिला लीडर्स की संख्या बढ़कर 117 हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है. इन महिलाओं की कुल संपत्ति 39 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो फिनलैंड की अनुमानित जीडीपी से भी अधिक है.

लेखिका सुधा मूर्ति, उद्यमी अनन्या बिरला, पत्रकार फे डिसूजा, पैरा ओलंपिक पदक विजेता अवनि लेखरा और अन्य कई महिलाओं ने अपनी-अपनी श्रेणियों में स्थान बनाया है. शहरों की बात करें तो मुंबई 26 महिला लीडर्स के साथ पहले स्थान पर है. दिल्ली में 21, बेंगलुरु में 16, गुरुग्राम में 6 और पुणे में 5 प्रभावशाली महिलाओं ने सूची में जगह बनाई है. रिपोर्ट यह भी बताती है कि 33 महिलाओं ने अपने करियर के लिए दूसरे राज्यों का रुख किया, जबकि दो महिलाओं ने विदेश जाकर अपनी पहचान बनाई.

रिपोर्ट के अनुसार, सूची में शामिल 98 महिलाएं (84%) सेल्फ-मेड हैं, यानी उन्होंने अपनी सफलता विरासत के बजाय अपने प्रयासों से हासिल की है. रिपोर्ट में 12 अलग-अलग श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को शामिल किया गया है. रोशनी नादर मल्होत्रा वेल्थ मल्टीप्लायर श्रेणी में शीर्ष पर हैं, जिनकी संपत्ति 2.84 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है.

ई-वे बिल के नए नियम फिलहाल टले, कारोबारियों को राहत

नई दिल्ली, 31 जुलाई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-वे बिल व्यवस्था में 1 अगस्त से लागू होने वाले दो महत्वपूर्ण बदलाव फिलहाल टाल दिए गए हैं. उद्योग जगत से मिले सुझावों और तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए जीएसटी नेटवर्क ने इन प्रस्तावित नियमों को स्थगित करने का फैसला लिया है. इससे व्यापारियों और परिवहन क्षेत्र को तत्काल राहत मिली है तथा फिलहाल ई-वे बिल की मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी.जीएसटी नेटवर्क ने उद्योग जगत से मिले फीडबैक के बाद ई-वे बिल प्रणाली में प्रस्तावित दो बदलावों को फिलहाल लागू नहीं करने का निर्णय लिया है. ये दोनों नियम 1 अगस्त 2026 से लागू होने वाले थे.

आईटीआर डेडलाइन पर कन्फ्यूजन खत्म

इस बार सभी टैक्सपेयर्स के लिए एक जैसी डेडलाइन नहीं

आय के स्रोत और आईटीआर फॉर्म के आधार पर अलग अंतिम तिथियां

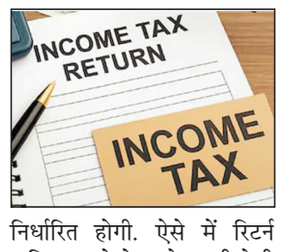

नयी दिल्ली, 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को लेकर इस बार बड़ी संख्या में करदाता असमंजस में हैं. कई लोगों को अब भी लगता है कि 31 जुलाई ही सभी के लिए आखिरी तारीख है, जबकि नए नियमों के तहत अलग-अलग श्रेणी के करदाताओं के लिए अलग-अलग अंतिम तिथियां तय की गई हैं.

पटना के चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि आईटीआर की डेडलाइन करदाता की आय के स्रोत और संबंधित आईटीआर फॉर्म के अनुसार निर्धारित होगी. ऐसे में रिटर्न दाखिल करने से पहले अपनी श्रेणी की पुष्टि करना जरूरी है. सीए अभिषेक मिश्रा के अनुसार, इस बार आयकर विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के लिए अलग-अलग अंतिम तिथियां तय की हैं. जिन लोगों की आय मुख्य रूप से वेतन, पेंशन या मकान किराये से होती है और जो आईटीआर-1 या आईटीआर-2 भरते हैं, उनके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है. वहीं, व्यवसाय से आय अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है. जिन कारोबारियों के खातों का ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए 31 अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े मामलों में अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है.

यदि कोई करदाता निर्धारित समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं कर पाता है, तो वह 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है. हालांकि, इसके लिए आयकर नियमों के अनुसार लेट फीस देनी होगी. कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक होने पर अधिकतम 5,000 रुपये और 5 लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 रुपये तक की लेट फीस लागू होगी.

एप्पल ने तीसरी तिमाही में बनाया कमाई का नया रिकॉर्ड

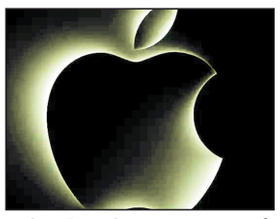

नयी दिल्ली, 31 जुलाई अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने भारत समेत सभी बाजारों में राजस्व का तीसरी तिमाही का नया रिकॉर्ड बनाया है.

कंपनी ने गुरुवार को कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में इस साल 27 जून को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा की. इस दौरान 109.4 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है. सकल लाभ मार्जिन 50.1 प्रतिशत रहा. प्रति शेयर आय 2.02 डॉलर रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है.

एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक ने परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि कंपनी ने सभी भौगोलिक क्षेत्रों में जून तिमाही के लिए राजस्व का नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इनमें लातिन अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, भारत, चीन, जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया शामिल हैं. उन्होंने विकसित और उभरते हुए बाजारों में समान रूप से नया रिकॉर्ड बनाने पर खुशी जाहिर की. एप्पल के निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर 0.27 डॉलर नकद लाभांश घोषित किया है.

बढ़त के साथ खुले शेयर बाजार

मुंबई, 31 जुलाई घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में तेजी रही, हालांकि आईटी और एफएमसीजी सेक्टरों में बिकवाली चल रही है. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 70.51 अंक की मजबूती के साथ 77,998.66 अंक पर खुला. कुछ देर के लिए यह लाल निशान में भी उतरा, लेकिन फिर वापसी करता हुआ खबर लिखे जाते समय यह 10.31 अंक (0.01 प्रतिशत) ऊपर 77,938.46 अंक पर रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 44.30 अंक की तेजी के साथ 24,361.45 अंक पर खुला. खबर लिखे जाते समय यह 20.45 अंक यानी 0.08 प्रतिशत की बढ़त में 24,337.60 अंक पर था. वृहत बाजार में तेजी बनी हुई है.

कम उम्र में जीवन बीमा खरीदना सबसे बेहतर वित्तीय फैसला क्यों है?

मुंबई, 31 जुलाई. श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ, श्री कैस्परुस जे.एच. क्रॉमहाउट जीवन बीमा वह विषय नहीं जिस पर लोग सुबह की चाय या कॉफी के साथ सोचते हों. आमतौर पर यह बात तब ध्यान में आती है जब जीवन में शांत या गंभीर पल सामने आते हैं. जैसे परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती हो जाए, किसी दोस्त के घर बच्चा हो जाए, या कोई वित्तीय फॉर्म भरते समय निवेश की जानकारी देनी हो.

ऐसे समय आप ठहरकर सोच सकते हैं, 'क्या मैं जीवन बीमा लेने के लिए अभी बहुत छोटा हूं? लेकिन सच यह है कि जीवन बीमा लेने का सबसे अच्छा समय वही है जब यह आप जरूरत महसूस होने से पहले ही इसे ले लें. क्योंकि तब यह सबसे सस्ता होता है. प्रीमियम भी कम देना पड़ता है. हालांकि कम प्रीमियम के अलावा भी कम उम्र में बीमा लेने के कई फायदे हैं.

कैस्परुस जे.एच. क्रॉमहाउट
श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ

भारत की युवा पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार, देश की 37.14% आबादी 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग की है. यह कुल आबादी का 27.3% है. यह आर्थिक रूप से सक्रिय लोगों का एक बड़ा हिस्सा है. इसके बावजूद भारत में जीवन बीमा की पहुंच अभी भी कम है. अलबत्ता यह कम हो रही है. यह वित्त वर्ष 2023 में 3% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 2.8% रह गई. इसका मतलब है कि देश के युवाओं का बड़ा हिस्सा अब भी कम बीमित या बिना बीमा के है. इस अंतर की एक वजह यह है कि लोग जीवन बीमा को सुरक्षा के साधन के बजाय बचत के प्रॉडक्ट के रूप में देखते हैं. यह धारणा भी है कि जीवन बीमा सिर्फ बुजुर्गों के लिए होता है और इसे 'बाद में' लिया जा सकता है. आम तौर पर लोग शादी, घर खरीदने या बच्चे होने जैसे अवसरों पर बीमा लेने का सोचते हैं. आज की युवा पीढ़ी इन फैसलों को भी देर से ले रही है. इसलिए उन्हें इसकी तुरंत जरूरत महसूस नहीं होती. लेकिन जीवन बीमा सिर्फ कम उम्र में एक समझदारी भरा फैसला ही नहीं है, बल्कि यह आपके लंबे समय के वित्तीय नियोजन में बड़ा बदलाव ला सकता है.

कम प्रीमियम को लंबे समय के लिए लॉक करना- जीवन बीमा का प्रीमियम आपकी उम्र और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है. कम उम्र में आप कम जोखिम वाले ग्राहक माने जाते हैं क्योंकि आप अपेक्षाकृत स्वस्थ होते हैं. इससे कम प्रीमियम पर ज्यादा लाभ मिलता है और पॉलिसी की मंजूरी भी आसान हो जाती है.

कैश वैल्यू के जरिए लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण- कुछ जीवन बीमा योजनाएं, जैसे एंडोमेंट प्लान या यूलिप, बचत या निवेश का हिस्सा भी रखती हैं. इससे समय के साथ नकद मूल्य बनता है.

कर्ज प्रबंधन में मदद

कम उम्र में ली गई जीवन बीमा पॉलिसी सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देती, बल्कि भविष्य में कर्ज प्रबंधन का साधन भी बन सकती है. अनिवार्य लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद कुछ पॉलिसियों, जैसे एंडोमेंट प्लान और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के खिलाफ सरेंडर वैल्यू पर लोन लिया जा सकता है. पॉलिसी के प्रकार और सरेंडर वैल्यू के अनुसार लोन आमतौर पर 50% से 90% तक मिल सकता है. इससे बिना निवेश तोड़े तुरंत धन की व्यवस्था हो जाती है. साथ ही इसमें तेज मंजूरी, कम ब्याज दर और लचीला भुगतान जैसे फायदे मिलते हैं. इस तरह यह आपात स्थितियों में एक अहम वित्तीय सहारा बनता है और परिवार की दीर्घकालिक सुरक्षा भी बनी रहती है.

आरईसी-पीएफसी का मेजा परियोजना से समझौता

नई दिल्ली, 31 जुलाई आरईसी लिमिटेड और पीएफसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसई और प्रमुख आधारभूत संरचना वित्तपोषण एनबीएफसी, ने मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड (एमयूएनपीएल) के साथ सामान्य ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम है.

इस समझौते के तहत कुल 26,850 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा. यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) प्रणाली के साथ स्टेज-II (3×800 मेगावाट) के तहत 800 मेगावाट की 2400 मेगावाट की मेजा टीपीपी स्टेज-II अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल इकाइयों की स्थापना के लिए दिया जाएगा, जिसकी अनुमानित परियोजना पूर्णता लागत 38,357.81 करोड़ रुपये हऋण दस्तावेजों पर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में एमयूएनपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री श्रीनिवास राव गद्दामनुगु, आरईसी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के मुख्य महाप्रबंधक शंभू शंकर गुप्ता और पीएफसी की जीएम सुश्री शैली गुप्ता ने एमयूएनपीएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री अंशु बरुआ, पीएफसी के कार्यकारी निदेशक श्री एच. के. दास और आरईसी के कार्यकारी निदेशक डी. बी. लोंधे की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए. प्रस्तावित 3×800 मेजा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (स्टेज II) एक साथ कई फायदे लेकर आएगा.

यह उत्तर प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, घरों, खेतों और उद्योगों के लिए भरोसेमंद बिजली सुनिश्चित करेगा और राज्य के बड़े विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा.

वंदे भारत से पहुंचा जीवित हृदय पहली बार

भारतीय रेल ने रचा इतिहास, यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट में होगा प्रत्यारोपण

अहमदाबाद, 31 जुलाई. भारतीय रेल ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से जीवित हृदय का सफलतापूर्वक परिवहन किया.

सूरत से अहमदाबाद तक हृदय को ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस से सुरक्षित एवं निर्धारित समय में पहुंचाया गया. इस हृदय का प्रत्यारोपण यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद में किया जाएगा. यह अत्यंत संवेदनशील और समयबद्ध जीवनरक्षक अभियान भारतीय रेल, गुजरात राज्य पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल तथा चिकित्सा टीमों के बीच उत्कृष्ट समन्वय का उदाहरण रहा. हृदय को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर तक सुरक्षित एवं निर्बाध रूप से पहुंचाने के लिए और गुजरात राज्य पुलिस द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया.

इसके माध्यम से अंग को निर्धारित समयसीमा के भीतर अस्पताल पहुंचाया गया, ताकि प्रत्यारोपण प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो. मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश ने कहा, 'यह भारतीय रेल के लिए अत्यंत गर्व और संतोष का क्षण है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से एक जीवित हृदय को सूरत से अहमदाबाद तक सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया गया. ऐसे जीवनरक्षक मिशन में समय का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण होता है.

समाचार विशेष

कुलदीप माइती को बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी

राज्यसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी ने पूरी ताकत से कमर कसी

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी राज्यसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है. बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस समय कई सीट को लेकर भाजपा कोर टीम के साथ बैठक कर रहे हैं. हाल में 4 टीएमसी राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं. ये सांसद भाजपा जॉइन कर उच्च सदन पहुंच चुके हैं.

चौथी सीट को लेकर राजनीति गहमागहमी तेज हो गई है दिसंबर 2026 तक कई सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है. उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से कमर कस ली है. पार्टी ने ऐलान किया है कि इस चुनाव में कुलदीप माइती अहम भूमिका निभाएंगे. कुलदीप माइती ने कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है. टीएमसी की तुष्टिकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार और कुशासन से लोग त्रस्त हो चुके हैं. कैग रिपोर्ट ने भी ममता बनर्जी सरकार की पोल खोल दी है. जनता के पैसे की लूट अब और बर्दाश्त नहीं होगी.

क्या बोले कुलदीप माइती- कुलदीप माइती ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. लेकिन बंगाल में ममता दीदी विकास के नाम पर सिर्फ धोखा दे रही हैं. विधानसभा उपचुनाव में जनता इसका जवाब वोट से देगी. कुलदीप माइती ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी खजाने में घोटाला, शिक्षा और स्वास्थ्य में धांधली, ये सब कैग रिपोर्ट में साफ है. भाजपा चुप नहीं बैठेगी.

कुलदीप माइती कौन

कुलदीप माइती पूर्वी भारत की प्रमुख माइक्रोफाइनेंस कंपनी वीएसएफ कैपिटल लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं. उन्हें माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में एक अनुभवी सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पर जाना जाता है. उनकी अगुवाई में कंपनी ने पूर्वी भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और वर्तमान में 14 राज्यों में लगभग 280 शाखाओं के माध्यम से चार लाख से अधिक महिला ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रही है.

प्रहलाद जोशी के जरिए बड़ा संदेश

नई दिल्ली. ऐसी चर्चा थी कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उनकी जगह शिक्षा का प्रभार दिया जाएगा. यह अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान वे सक्रिय भूमिका निभा रहे थे.

प्रधानमंत्री आवास के सामने राहुल गांधी के प्रदर्शन के दौरान भी वे दो बार राहुल से बात करने गए थे. उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी से दोबारा बात शुरू हुई तो उनको भी वार्ता में शामिल किया गया. पहले दौर की वार्ता अकेले जेपी नड्डा ने की थी, जो बेनतीजा रही थी. हालांकि प्रधान का इस्तीफा हुआ तो शिक्षा मंत्रालय का प्रभार प्रहलाद जोशी को सौंप दिया गया. फिर भी पेपर लीक और नकल रोकने के लिए लाए गए संविधान संशोधन बिल को जितेंद्र सिंह ने सदन में पेश किया. वे इस पर विस्तार से बात रखेंगे. यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह भी इस पर बोलेंगे.

ऐसा लग रहा है कि सरकार ने सोच लिया था कि धर्मेंद्र प्रधान विदा होंगे तो किसी अगड़ी जाति के नेता को शिक्षा का प्रभार दिया जाएगा. तभी जितेंद्र सिंह का नाम चला और प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार मिला.

इंस्टाग्राम की राजनीति में कौन आगे?

जयपुर. नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद के दौरान सोशल मीडिया पर चले देशव्यापी अभियान और युवाओं की डिजिटल सक्रियता ने एक बार फिर यह साबित किया कि आज राजनीतिक विमर्श का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर ही तय हो रहा है.

यही वजह है कि अब नेताओं की लोकप्रियता केवल जनसभाओं या चुनावी रैलियों से नहीं, बल्कि उनके डिजिटल प्रभाव और सोशल मीडिया एंगेजमेंट से भी आंकी जा रही है. जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से सोशल मीडिया को केवल प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि जनता से सीधे संवाद का सबसे प्रभावी प्लेटफॉर्म बताते रहे हैं. जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद देशभर में उद्वेलित युवाओं की स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय कैबिनेट बैठक में नेताओं के लिए इंस्टाग्राम पर प्रभावी मौजूदगी को लेकर भी बातचीत हुई थी. इसके बाद भाजपा संगठन और सरकार के स्तर पर भी नेताओं को इंस्टाग्राम, रील्स और शॉर्ट वीडियो के जरिए युवाओं तक पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है.

राजस्थान में इंस्टा पॉलिटिक्स बड़ी रोचक - राजस्थान की राजनीति पर नजर डालें तो इंस्टाग्राम के आंकड़े एक बेहद दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं. कुछ नेता सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं, जबकि राज्य मंत्रिमंडल के आधे से अधिक मंत्री ऐसे हैं जो अभी तक 50 हजार फॉलोअर्स का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि प्रदेश की राजनीति में डिजिटल मौजूदगी अभी भी बेहद असमान है. राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इंस्टाग्राम पर सबसे लोकप्रिय मंत्री के रूप में सामने आते हैं.

टॉप लीडर्स के फॉलोअर्स

विपक्ष की ओर से पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट भी लगभग 12 लाख फॉलोअर्स के साथ मुख्यमंत्री के बराबर मजबूत डिजिटल पकड़ बनाए हुए हैं. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 11 लाख और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 10 लाख फॉलोअर्स के साथ प्रदेश के सबसे प्रभावशाली डिजिटल नेताओं में शामिल हैं. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के करीब 7.39 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा 3.61 लाख और कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा 3.12 लाख फॉलोअर्स के साथ अच्छी डिजिटल मौजूदगी रखते हैं.

विशेष | निषाद समाज को संवैधानिक अधिकार मिलने तक संघर्ष

मुकेश सहनी ने फूंका आरक्षण का बिगुल

बागपत. विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक एवं बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत में आयोजित कार्यकर्ता संवाद एवं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए निषाद-कश्यप समाज से अपने अधिकारों और आरक्षण की लड़ाई को निर्णायक चरण तक पहुंचाने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी का उद्देश्य समाज को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तथा जब तक निषाद समाज को उसका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा.

मुकेश सहनी ने कहा कि उनका जन्म एक अत्यंत गरीब मछुआरा परिवार में हुआ और कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए उन्होंने मुंबई में सफलता हासिल की. उन्होंने कहा कि समाज की बदहाली देखकर उन्होंने अपना कारोबार और सुख-सुविधाएं छोड़कर सार्वजनिक जीवन का रास्ता चुना. पिछले 12 वर्षों से वह बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के सम्मान, आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में वीआईपी ने अपनी ताकत साबित की और कम समय में सरकार का हिस्सा बनकर समाज की आवाज बुलंद की. उन्होंने आरोप लगाया कि निषाद समाज के अधिकारों की मांग उठाने के कारण उन्हें सत्ता से बाहर किया गया. उन्होंने कहा कि यदि वह समझौता कर लेते तो आज भी मंत्री बने रहते, लेकिन उन्होंने समाज के सम्मान को सत्ता से ऊपर रखा.

वीआईपी संस्थापक ने समाज से आह्वान किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्येक गांव में गंगाजल हाथ में लेकर यह संकल्प लिया जाए कि यदि निषाद-कश्यप समाज को आरक्षण नहीं मिलता है तो भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस संकल्प अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने और इसके वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित करने की अपील की.

समाज के हित सर्वोपरि

मुकेश सहनी ने कहा कि आजादी के दशकों बाद भी निषाद समाज अपना राष्ट्रीय नेतृत्व खड़ा नहीं कर सका, जबकि अन्य समाजों ने अपने नेतृत्व को मजबूत कर राजनीतिक अधिकार हासिल किए. उन्होंने कहा कि समाज को शिक्षा, संगठन और राजनीतिक जागरूकता को प्राथमिकता देनी होगी. उन्होंने युवाओं से पंचायत से लेकर संसद तक अपनी भागीदारी बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि केवल वोट की ताकत से ही समाज अपने अधिकार सुनिश्चित कर सकता है. उन्होंने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें निषाद समाज को आरक्षण देने में विफल रहती हैं तो वीआईपी पार्टी आगे की राजनीतिक रणनीति तय करेगी.